



◆ छत्तीसगढ़ के लिए ◆
मोदी की गारंटी
2023



सशक्त छत्तीसगढ़ के लिए
भाजपा को वोट दें



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़





श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित



“

जय जोहार, जय छत्तीसगढ़

भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं को समझा और राज्य के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का निर्णय लिया था। भाजपा की राज्य सरकार ने 15 वर्षों में एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ को एक गरीब और पिछड़े राज्य से एक विकसित और समृद्ध राज्य में बदला और छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में काम किया।

आज भाजपा का यह घोषणापत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ को और विकसित, समृद्ध एवं समावेशी बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इस घोषणापत्र में भाजपा सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

पिछले पाँच सालों में छत्तीसगढ़ ने झूठे वादों से सत्ता में आई सरकार के कपट और कुशासन को देखा, जिसने 15 साल की मेहनत से सम्पन्न हुए राज्य को फिरसे पीछे धकेलने का काम कर जनता का विश्वास खो दिया है। पर भाजपा के कार्यकाल में जनता को विकास और अपने वचन के प्रति सरकार की ऐसी प्रतिबद्धता दिखी थी जिसपर आज भी जनता का विश्वास है। छत्तीसगढ़ की जनता इस घोषणापत्र में अपने वादों पर खरे उत्तरने वाली विश्वसनीय भाजपा सरकार की राज्य में परिवर्तन लाने की योजनाओं को देखेगी। राज्य में भाजपा के पुनः आगमन के साथ छत्तीसगढ़ में एक नए युग का प्रारम्भ होगा, जहाँ महिलाओं से लेकर किसानों तक हर कोई समृद्धि की ओर अग्रसर एवं सशक्त होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा बदलाव सुनिश्चित करने के लिए जनता ने तय कर लिया है कि वह इस बार परिवर्तन जरूर लेकर आएगी।

अंत में, मैं छत्तीसगढ़ के प्रिय भाइयों और बहनों से यह अपील करता हूँ कि आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर ले चलें। भाजपा छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए, हम सब इस विकास यात्रा में शामिल हों और छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार बनाएँ।

”

श्री अरुण साव

प्रदेश अध्यक्ष



“

छत्तीसगढ़ महातारी की जय

देश के आजादी काल से छत्तीसगढ़ के महापुरुषों ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सम्यता एवं समावेशी विकाश के दृष्टीकोण से अलग छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी। इस कल्पना को आजादी के 53 साल बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवम्बर 2000 को साकार किया, जिस के लिए छत्तीसगढ़वासी सदा उनके आभारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद इन 23 सालों में भाजपा ने डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़वासियों की अनंत आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए समावेशी विकास किये। एक राजनैतिक पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र "सर्व हिताय, सर्व सुखाय" की भावना को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जनता के कल्याण के लिए हर वर्ग को समाहित करते हुए जनता के मन में विश्वास को अर्जित कर इस घोषणा पत्र को तैयार किया है।

हमनें घोषणा पत्र तैयार करते समय एक वृहद रूपरेखा तैयार की, जिसके तहत प्रदेश के 90 विधानसभाओं में 90 मतपेटियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ियों के मन की बात को सुझाव पेटी में डालने का अनुरोध किया। इसके अलावा व्हाट्सऐप और ईमेल के जरिए भी छत्तीसगढ़वासियों के सुझाव प्राप्त हुए। प्रत्येक विधानसभा से सभी वर्ग के लोगों ने विभिन्न माध्यमों से एक उम्मीद और विश्वास के साथ हमें सुझाव दिए जिसकी संख्या लगभग दो लाख है।

छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने हमारे प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसान, महिलाएं, युवा, व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर, अधिवक्ता, पत्रकार, खिलाड़ी, कलाकार, सभी जाति और समुदाय के लोग, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग, सभी ने अपने सुझाव दिए। हम इन सुझावों की सराहना करते हैं और इनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने घोषणा पत्र तैयार किया है, परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा पत्र हर छत्तीसगढ़ी के मन की बात है।

घोषणा पत्र समिति ने अनेक विषय विशेषज्ञों और पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर एकत्रित सभी सुझावों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। यह घोषणा पत्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के वचन और दर्शन, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" पर आधरित है। आज, इस महत्वपूर्ण पत्र के उद्घाटन के अवसर पर, इसे जनता जनार्दन को समर्पित कर, सभी नागरिकों को एकजुट होने और मिलकर एक बेहतर प्रदेश बनाने के लिए आह्वान करते हैं। एक ऐसा छत्तीसगढ़, जो सभी के लिए समृद्धि, समानता और न्याय का प्रतीक हो। एक ऐसा छत्तीसगढ़, जो दुनिया में अपनी अग्रणी भूमिका निभाए।

श्री विजय बघेल

”

संयोजक,
घोषणा पत्र समिति



માજપા છત્તીસગઢ ઘોષણા પત્ર સમિતિ

સંયોજક

શ્રી વિજય બધેલ

સહ સંયોજક

શ્રી રામિવચાર નેતામ

શ્રી અમર અગ્રવાલ

શ્રી શિવરતન શર્મા

સદસ્ય સચિવ

શ્રી પંકજ ઝા

સદસ્ય

સુશ્રી લતા ઉસેંડી
શ્રી ચંદ્રશેખર સાહુ
ડૉ. કૃષ્ણમૂર્તિ બાંધી
શ્રી રાજા રણવિજય સિંહ
શ્રી મધુસૂદન યાદવ
શ્રીમતી રંજના સાહુ
શ્રી મૈયાલાલ રાજવાડે
શ્રી મહેશ ગાગડા
શ્રી કમલભાન સિંહ
શ્રીમતી કમલા દેવી પાટલે
શ્રી ઓપી ચૌધરી
શ્રીમતી ચમ્પાદેવી પાવલે
શ્રી સંદીપ શર્મા
શ્રી કેદારનાથ ગુપ્તા

શ્રી ભરત વર્મા
શ્રી રવિ ભગત
શ્રીમતી વિભા અવસ્થી
ડૉ. વિજયશંકર મિશ્રા
શ્રી રામલખન સિંહ પૈકરા
શ્રી દીપક સાહુ
શ્રી આત્માનારાયણ પટેલ
શ્રી રામકૃષ્ણ ધીવર
શ્રી રામકુમાર ભટ્ટ
શ્રી દ્વારિકા જાયસવાલ
શ્રી ટેકેશ્વર જૈન
શ્રી વિક્રમ સિંહ
ડૉ. સલીમ રાજ



विषय सूची

मोदी गारंटी - प्रमुख वादे	01-04
समृद्धि किसान-सम्पन्न प्रदेश	05-08
जनजाति उत्थान -प्रदेश का मान	09-10
सर्वकल्याण की सोच	11-14
सशक्त समृद्धि सम्पन्न नारी	15-16
श्रमिक कल्याण - प्रदेश महान	17-18
विकसित गाँव - विकासशील प्रदेश	19-20
उत्तम स्वास्थ्य - सेहतमंद प्रदेश	21-22
बेहतर शिक्षा - उज्ज्वल भविष्य	23-26
वचनबद्ध सुशासन	27-30
मजबूत बुनियाद - अटूट संरचना	31-32
वैभवपूर्ण विरासत - वंदनीय छत्तीसगढ़	33-36
ऊर्जावान युवा - प्रगतिशील प्रदेश	37-40
व्यापार वृद्धि से प्रदेश की समृद्धि	41-44
प्राकृतिक संसाधन - प्रदेश का धन	45-47





कृषक उन्नति योजना

हम "कृषक उन्नति योजना" की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत:

- 21 किलोट्रिल प्रति एकड़ धान की खरीदी ₹3,100 में की जाएगी।
- किसानों का पैसा बिना लम्बी कतारों के एक ही किस्त में पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर स्थापित करेंगे।
- प्रदेश में धान खरीद से पहले ही बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।



01

महतारी वन्दन योजना

हम 'महतारी वन्दन योजना' की शुरुआत कर प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को ₹12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।



रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती

हम प्रदेश के 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित करेंगे।

02



03

18 लाख प्रधानमंत्री आवास एवं घर-घर निर्मल जल अभियान

हम अपनी पहली 'कैबिनेट बैठक' में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन-राशि का आवंटन करेंगे एवं 2 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगे।



तेंदूपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस

- हम प्रदेश में तेंदूपत्ता का संग्रहण ₹5,500 प्रति मानक बोरा में करेंगे।
- संग्रहण मौजूदा दिनों से बढ़ाकर 15 दिन तक किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त संग्राहकों को ₹4,500 तक बोनस, चरणपादुका एवं अन्य सुविधाएँ पुनः प्रदान की जाएंगी।

04





06

दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना

हम 'दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना' की शुरुआत कर प्रत्येक भूमिहीन खेतिहार मजदूर को हर साल ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।



आयुष्मान भारत - स्वस्थ छत्तीसगढ़

हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत वार्षिक सीमा को दोगुना करके प्रति परिवार को ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख का स्वास्थ्य बिमा प्रदान करेंगे एवं हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र सुनिश्चित कर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे।

07



08

पी.एस.सी. परीक्षा में पारदर्शिता

हम राज्य में हुए पी.एस.सी. घोटाले की जांच करवाएंगे एवं सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को UPSC की तर्ज पर सुव्यवस्थित करेंगे।



09

छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

हम "छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना" के तहत प्रदेश में युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे।



10

स्टेट कैपिटल रीजन (SCR)

हम नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली (NCR) की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की स्थापना कर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करेंगे।





11

इनोवेशन हब

हम नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बना कर राज्य में 6 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे।



12

रानी दुर्गावती योजना

हम प्रदेश में 'रानी दुर्गावती योजना' की शुरुआत कर BPL वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर ₹1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी करेंगे।



13

₹500 में सिलिंडर

हम गरीब परिवारों की महिलाओं को ₹500 में गैस सिलिंडर प्रदान करेंगे।



14

मासिक ट्रेवल अलॉवंस

हम छात्रों को कॉलेज आने-जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलॉवंस प्रदान करेंगे।



15

भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग

भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेंस नीति -

1. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करेंगे।
2. भ्रष्टाचार शिकायत निवारण व निगरानी रखने के लिए एक वेब पोर्टल बनाएंगे।
3. प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे।





16

CIMS एवं CIT



हम छत्तीसगढ़ के हर संभाग में एस की तर्ज पर **छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (CIMS)** एवं हर लोकसभा क्षेत्र में आई.आई.टी. की तर्ज पर **छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CIT)** का निर्माण करेंगे।

17

इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मलेन

हम इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर **इन्वेस्ट छत्तीसगढ़** आयोजित करेंगे और **वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मलेन** कर **देशी व विदेशी कंपनियों** से **निवेश आमंत्रित** करेंगे।



18

सरकार तुंहर दुवार



हम प्रदेश में "**सरकार तुंहर दुवार**" योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर **1.5 लाख बेरोज़गार युवकों** को भर्ती कर प्रभावी **घर पहुँच सार्वजनिक सेवा** सुनिश्चित करेंगे।

19

शक्ति-पीठ परियोजना

हम प्रदेश में **1,000 किलोमीटर लंबी 'शक्ति-पीठ परियोजना'** की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के पांच शक्ति पीठों को उत्तराखण्ड की चार धाम परियोजना की तर्ज पर विकसित करने और जोड़ने का काम करेंगे।



20

श्रीरामलला दर्शन



हम प्रदेशवासियों को **श्रीरामलला** के दर्शन कराने हेतु अयोध्या लेकर जाएंगे।

समृद्ध किसान-सम्पन्न प्रदेश



हम ही कर रहे हैं



प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 38 लाख से ज्यादा किसानों के लिए ₹6,757 करोड़ जारी किए।



प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ में ₹396.97 करोड़ की परियोजनाएँ प्रारम्भ की गईं।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का कृषि बजट 6 गुना तक बढ़ाया गया।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस कुशासन में प्रदेश के 700 किसानों ने आत्महत्या की।
- गौठानों में भूपेश बघेल सरकार ने ₹1,300 करोड़ का धोटाला किया।
- भूपेश बघेल सरकार ने 1 लाख 61 हज़ार किसानों को पीएम-किसान के लाभ से बंचित रखा।





हमारा वादा

01

हम “कृषक उन्नति योजना” की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत:

1. 21 किंविंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी ₹3,100 में की जाएगी।
2. किसानों का पैसा बिना लम्बी कतारों के एक ही किस्त में पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर स्थापित करेंगे।
3. प्रदेश में धान खरीद से पहले ही बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

02

हम ‘दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना’ की शुरुआत कर प्रत्येक मूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

03

हम 2016-17 एवं 2017-18 के खरीफ़ सीज़न के लिए बकाया धान खरीदी बोनस का प्रत्येक किसान का उचित हिस्सा ₹300 प्रति किंविंटल राष्ट्रीय सुशासन दिवस (25 दिसंबर) पर भुगतान करेंगे।

04

हम गन्ना किसान एवं मिल कानून लागू कर समयबद्ध भुगतान और बाजार में उतार-चढ़ाव न होना सुनिश्चित करेंगे।

05

हम मक्के के उपार्जन को सरलीकृत कर उसमें वृद्धि करेंगे।

06

हम ₹150 करोड़ का ‘कृषि इनपुट मूल्य स्थिरीकरण कोष’ बनाकर खाद एवं कीटनाशकों की कीमत में उतार-चढ़ाव नहीं होने देंगे।

07

हम ‘कृषि बलराम योजना’ की शुरुआत कर हर तीन ग्राम पंचायतों में एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एवं उसके साथ एक कृषि समृद्धि केंद्र स्थापित कर ‘बीज से बाजार तक’ मॉडल के तहत किसानों को हर कदम पर सहायता प्रदान करेंगे।



08

हम 'कृषि विद्या निधि योजना' की शुरुआत कर छोटे और सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को स्नातकोत्तर तक ₹2,00,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

09

हम हर तीन ग्राम पंचायतों के लिए एक **धान उपार्जन केंद्र** सुनिश्चित करेंगे।

10

हम किसानों के लिए **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** के जरिए **उत्तम गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता** सुनिश्चित करेंगे जिसमें राज्य सरकार द्वारा **लागत का आधा हिस्सा** प्रदान किया जाएगा।

11

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में धान की खरीदी **इलेक्ट्रॉनिक कांटों** के माध्यम से ही हो।

12

हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान और खेतिहर मजदूर को ₹5 लाख का **बिना किसी लागत की जीवन बीमा कवर** और ₹5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेंगे।

13

हम प्रदेश में एक **विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय** की स्थापना करेंगे।

14

हम **चरी-चरावन की समस्या का समाधान** कर फसल संरक्षण हेतु पारम्परिक गौ चरवाहों को **प्रोत्साहन राशि** एवं किसानों को तार फेंसिंग के लिए **सब्सिडी** प्रदान करेंगे।

15

हम 2025 तक पूरा करने के लक्ष्य से 'कोडार-सिकासेर बांध इंटरलिंकिंग परियोजना' की शुरुआत कर गरियाबंद और महासमुंद जिलों तक **नहर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार** सुनिश्चित करेंगे।



16

हम हर ब्लॉक में एक 'दूध संग्रहण केंद्र' एवं हर जिले में एक 'चिलिंग केंद्र' स्थापित कर किसानों को दूध संग्रह में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करेंगे इसके अतिरिक्त, दूध के संग्रहण हेतु खरीद मूल्य प्रदान किया जाएगा।

17

हम एक नई 'मत्स्य पालन नीति' शुरू कर राज्य के मछुआरा समूहों को उनका पारम्परिक अधिकार देंगे।

18

हम मधुमक्खी के छत्ते और मधुमक्खी कॉलोनी स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी देने का प्रावधान करेंगे।

19

हम प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का प्रभावी क्रियान्वन सुनिश्चित करते हुए जैविक खेती और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देंगे।

20

हम अधिया, रेक और ठेक पर काम कर रहे किसानों का न्यायिक हिस्सा सुनिश्चित करने हेतु शासकीय एग्रीमेंट अनिवार्य करेंगे।



जनजाति उत्थान - प्रदेश का मान



हमने किया



भाजपा सरकार ने **तेंदूपत्ता संग्रहण** दर प्रति बोरी 2003 में ₹450 से बढ़ाकर 2018 में ₹2,500 किया।



भाजपा सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए **आरक्षण कोटा** 20% से बढ़ाकर **32%** कर दी।



2010 में '**प्रयास कार्यक्रम**' के तहत जनजातीय छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईआईटी की **निःशुल्क कोचिंग** सुविधा देने की शुरुआत की गई।

हम ही कर रहे हैं



2014 से सरकार ने जनजाति समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कुल ₹89,000 करोड़ आवंटित किए हैं।



केंद्र की भाजपा सरकार ने **श्रीमती द्वौपदी मुर्मू जी** को जनजातीय समुदाय से पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना।



1997-98 में, वाजपेयी सरकार ने **दूरदराज** के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करने के लिए **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय** (ईएमआरएस) की शुरुआत की।

कांग्रेस का धोखा

- भाजपा सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहकों के कल्याण के लिए संचालित चरणपादुका योजना कांग्रेस द्वारा बंद की गई।
- कांग्रेस सरकार ने 2019 के बाद से तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि नहीं की है एवं संग्रहण के दिन भी कम कर दिए।
- कांग्रेस ने धर्मात्मण गतिविधियों पर ध्यान न देकर जनजाति संस्कृति को नष्ट करने की साजिश रची।





हमारा वादा

01

तेंदूपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस

1. हम प्रदेश में **तेंदूपत्ता का संग्रहण ₹5,500 प्रति मानक बोरा** में करेंगे।
2. संग्रहण **मौजूदा** दिनों से बढ़ाकर 15 दिन तक किया जाएगा।
3. इसके अतिरिक्त संग्राहकों को ₹4,500 तक बोनस दिया जाएगा।
4. **चरणपादुका** एवं अन्य सुविधाएँ पुनः प्रदान की जाएंगी।

02

हम राज्य के **प्रत्येक जनजातीय परिवार** को आजीविका में बढ़ोतरी हेतु **2 बकरियां** देंगे।

03

हम प्रदेश में एक **समग्र रूपरेखा** तैयार करेंगे जिसके अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए **छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं** और **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं** शामिल होंगी। इसके अंतर्गत तेंदू पत्ता संग्राहकों को उचित **मुआवजा** एवं आगे बढ़ने के लिए आवश्यक **संसाधनों** तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी।

04

हम **फड़ मुंशीयों** को **कमीशन** के अतिरिक्त ₹25,000 वार्षिक मानदेय प्रदान करेंगे।

05

हम जनजाति कल्याण हेतु **5 लाख वनाधिकार पट्टे** वितरित करेंगे।

06

हम आदिवासी छात्रों के लिए **100 विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय** बनाएंगे।

07

हम प्रदेश में '**महुआ खरीद नीति**' बनाकर महुआ के व्यापार को सुलभ बनाएंगे एवं प्रदेश में '**महुआ अनुसंधान और विपणन केंद्र**' के माध्यम से नए तकनीकों का इस्तेमाल कर महुआ उत्पाद में बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही **स्थानीय लोगों** को **रोजगार** प्रदान कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।

08

हम छत्तीसगढ़ में '**इमली खरीद नीति**' बनाएंगे एवं '**इमली अनुसंधान और विपणन केंद्र**' के माध्यम से नए तकनीकों का इस्तेमाल कर **इमली** के उत्पाद में बढ़ोतरी करेंगे।

09

हम हर्रा, साल बीज, इमली, इमली बीज और इमली के फूल का संग्रहण दर बढ़ाएंगे, इसके अतिरिक्त इन वनोपजों के संग्राहकों के लिए **बोनस एवं अन्य प्रोत्साहन** भी सुनिश्चित किया जाएगा।

10

हम प्रदेश में **प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना** के क्रियान्यवन से जनजातीय कृषकों के **फसल की सीधी खरीद** सुनिश्चित करेंगे।



सर्वकल्याण की सोच



हमने किया



पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में **विश्व प्रसिद्ध चावल वितरण योजना** की शुरुआत कर प्रदेश के हर परिवार तक अन्न पहुंचाने का काम किया।



2015 में मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में **सात विशेष रूप** से पिछड़े जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए **11-सूचीय कार्यक्रम** तैयार किया था।



अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए **आश्रमशाला**, छात्र भोजन सहाय योजना, विशेष कोचिंग केंद्र योजना, एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना समेत ढेरों योजनाएं चलायी गईं।

हम ही कर रहे हैं



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को पहला ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री और 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री मिले।



राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही ₹157.9 करोड़ की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई।



राज्य में 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गावों को प्रतिवर्ष विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस सरकार में अनुसूचित जाति के खिलाफ होने वाले **अपराध** के मामलों में 25% का इजाफा हुआ।
- कांग्रेस सरकार के अनुसूचित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों के कल्याण के ऊपर उदासीन रवैया अपनाने के कारण प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 17.3% की भारी गिरावट लाई है।
- कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सताया जा रहा है।



हमारा वादा

01

हम अपनी पहली 'कैबिनेट बैठक' में **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत **लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा** करने के लिए **धन-राशि** का आवंटन करेंगे।

02

हम प्रदेश में '**रानी दुर्गावती योजना**' की शुरुआत कर **BPL वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर ₹1,50,000 का आश्वासन प्रमाण** पत्र जारी करेंगे।

03

हम प्रदेश में शिल्पकारों और कारीगरों के हित में **पीएम विश्वकर्मा योजना** के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ में वृद्धि करेंगे एवं '**पौनी पसारी समृद्धि योजना**' की शुरुआत कर **पारम्परिक व्यवसायियों को स्वरोज़गार** हेतु अनुदान प्रदान करेंगे।

04

हम प्रदेश के हर नागरिक को **अटल पेंशन योजना** के अंतर्गत पेंशन प्रदान करेंगे जिसमें योजना का आधा भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

05

हम प्रदेश में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु **हर संभाग में एक बाल केंद्र का निर्माण** करेंगे।

06

हम प्रदेश के **गरीब श्रेणी** के सभी छात्रों को **इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और सीए सहित प्रोफेशनल शिक्षा पाठ्यक्रमों** के लिए **50% तक की छात्रवृत्ति** प्रदान करेंगे।



07

हम प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को **बिना किसी लागत के आवास और भोजन** प्रदान कर उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए **सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर में छात्रावास** स्थापित करेंगे।

08

हम '**सशक्त दिव्यांग समृद्धि योजना**' की शुरुआत कर दिव्यांगों का समग्र विकास करेंगे, जिसके अंतर्गत:

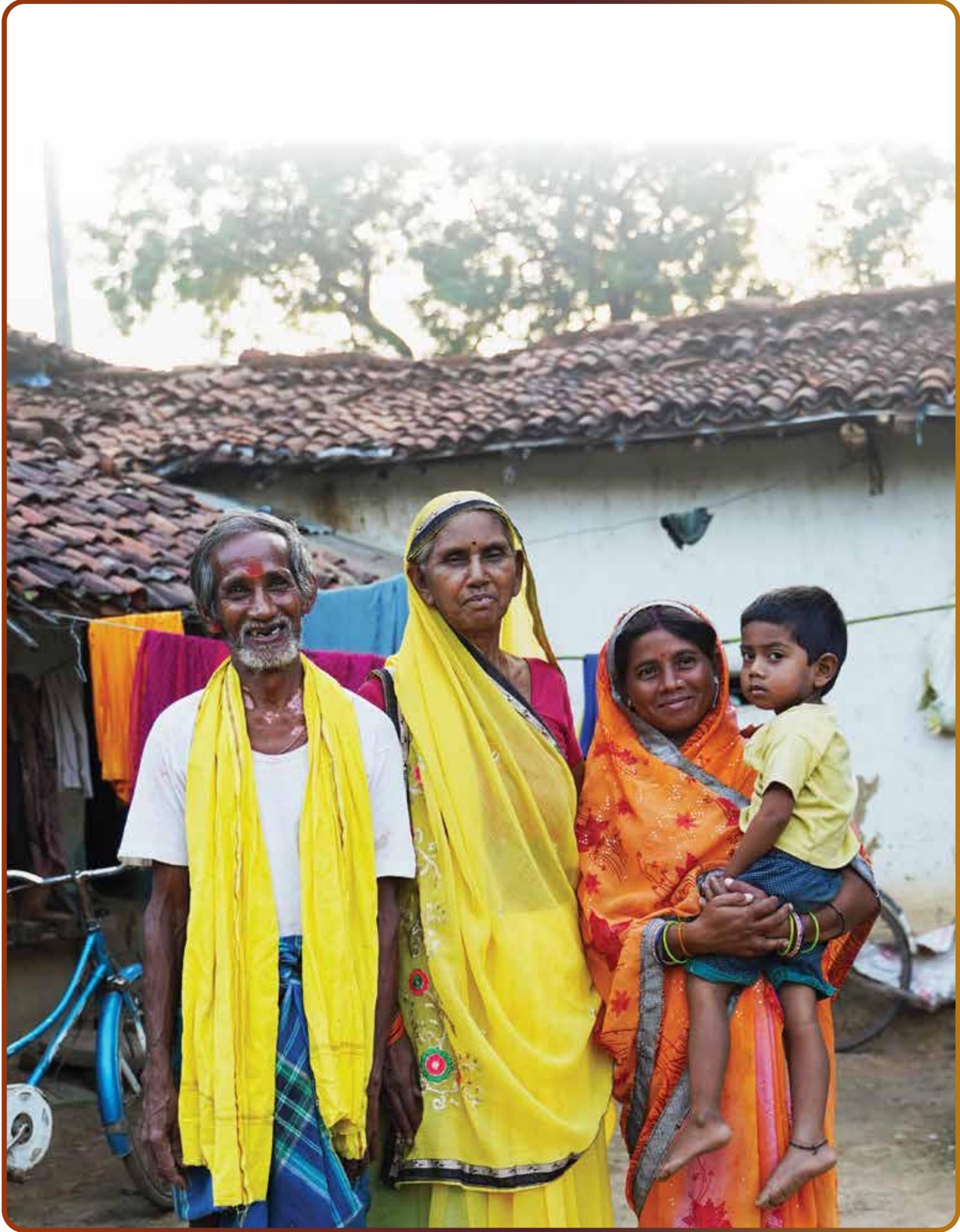
1. **दिव्यांग विकास आयोग** का गठन कर दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार सहायता सहित विकासात्मक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
2. '**सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान**' की शुरुआत कर प्रदेश के दिव्यांगों के सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग-अनुकूल करेंगे।
3. साथ ही प्रदेश में प्रत्येक **दिव्यांग छात्र** के लिए **छात्रावास सुविधाएं** एवं **विशेष स्कूल** स्थापित कर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुलभ बनाया जाएगा।

09

हम '**सर्वगुण-संपन्न योजना**' की शुरुआत कर प्रदेश के दिव्यांग बच्चों को **प्रारंभिक जांच** से लेकर **आजीवन सहायता** तक **संपूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सहायता** प्रदान करेंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भाग शामिल होंगे:

1. '**दिव्यांगजन समर्थ योजना**' की शुरुआत कर दिव्यांगता की शीघ्र पहचान के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और जिला अस्पताल को संपूर्ण जांच व पहचान सुविधाओं से लैस करना।
2. एक **परामर्शदाता, 'सहायक'** की उपस्थिति को सुनिश्चित कर दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को प्रत्येक पीएचसी में परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना।





भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी

सशक्त समृद्ध सम्पन्न नारी



— हमने किया —



भाजपा सरकार के 15 वर्षों में **मातृ मृत्यु दर आधी हुई**, यानी 2003 में 407 प्रति लाख जन्म से 2018 में **221 प्रति लाख जन्म** तक गिरावट हुई।



आयुष्मती योजना के तहत पीएचसी, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती होने वाली महिलाओं को बुनियादी जरूरतों के लिए **₹1,000 तक नकद** दिया जाता था।



स्नातक स्तर तक बालिकाओं की शिक्षा भाजपा सरकार में **निःशुल्क** कर दी गई।

हम ही कर रहे हैं



प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2023 तक छत्तीसगढ़ में 35 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन जारी किये गए।



मिशन इंद्रधनुष 2.0 के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में **महिलाओं एवं बच्चों** के लिए टारगेट के क्रमशः **103%** और **104%** का टीकाकरण कवरेज हासिल किया है।



प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के तहत छत्तीसगढ़ में अगस्त 2023 तक **2,07,369** गर्भवती महिलाओं और **1,22,806** स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभान्वित किया गया।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस सरकार में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतारी हुई है, कई मामलों में तो कांग्रेस नेता ही इन अपराधों में शामिल है।
- प्रदेश में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या दर 41.5% (2005-06) से बढ़कर **51.8%** (2020-21) हो गई है।
- प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कांग्रेस सरकार ने भुगतान नहीं किया और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को भी सही ढंग से नहीं बेचा।



हमारा वादा

01

हम 'महतारी वन्दन योजना' की शुरुआत कर प्रदेश की **प्रत्येक विवाहित महिला** को ₹12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

02

हम गरीब परिवारों की महिलाओं को ₹500 में **गैस सिलेंडर** प्रदान करेंगे।

03

हम प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु **महिला स्व-सहायता समूहों** को ₹5 लाख तक का **ऋण न्यूनतम ब्याज दर** पर प्रदान करेंगे एवं इन समूहों से **शासकीय अधिग्रहण** को प्राथमिकता दी जाएगी।

04

हम प्रदेश में **रेडी-टू-इंट योजना** की जिम्मेदारी फिर से **महिला स्व-सहायता समूहों** को देंगे, इसके अतिरिक्त इन महिलाओं को **सांत्वना राशि** भी दी जाएगी।

05

हम प्रदेश में महिलाओं के नाम पर कराए जा रहे **भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क** को 50% कम करेंगे।

06

हम 'नमो पोषण' (NAMO-POSHAN) की शुरुआत कर सरकारी स्कूलों के **कक्षा 1 से 8** तक के छात्रों को मध्यान्ह भोजन के **अतिरिक्त सुबह का नाश्ता** प्रदान करेंगे।

07

हम छत्तीसगढ़ में छात्राओं को **स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा** प्रदान करेंगे।

08

हम 'मातृत्व सुरक्षा योजना' की शुरुआत कर प्रत्येक गर्भवती महिला को ₹21,000 की लागत से 6 पोषण किट एवं **आर्थिक सहायता** प्रदान करेंगे तथा 'एनीमिया-मुक्त छत्तीसगढ़' बनाने हेतु, राज्य में IFA की पूर्ण खुराक सुनिश्चित की जाएगी।

09

हम **हर जिले में महिला (पिंक) थाने** स्थापित कर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।



श्रमिक कल्याण - प्रदेश महान



हमने किया



ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना की शुरआत कर ईलाज हेतु ₹50,000 की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।



2013 में श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना की शुरआत कर श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की।



माजपा सरकार द्वारा सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना की शुरआत कर इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सीए, एमबीए अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा हेतु विशेष कोचिंग शुल्क प्रदान किया गया।

हम ही कर रहे हैं



इ-श्रम पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के 83 लाख से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें पेंशन एवं बिमा का लाभ प्रदान किया गया।



अटल पेंशन योजना के तहत 2018 से 30 नवंबर 2022 के बीच 7,88,221 लाभार्थियों ने नामांकन कराया है।



प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अब तक 2,30,816 श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है।

कांग्रेस का धोखा

- छत्तीसगढ़ में मनरेगा दैनिक भत्ता देश में सबसे कम दरों में आता है।
- कांग्रेस सरकार की लापरवाही के चलते श्रमिकों के हुए सैकड़ों हादसे एवं मौतें।
- कन्या विवाह योजना एवं नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं बंद की गईं।



—हमारा वादा—

01

हम 'श्रमिक सुरक्षा बीमा योजना' शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्येक **ई-श्रम पंजीकृत असंगठित श्रमिक** को मुफ्त ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और ₹5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।

02

हम प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के लिए अन्य राज्य के महानगरों में '**मोर चिन्हारी भवन**' की स्थापना कर जरूरी सहायक एवं आर्थिक सहयोग सुविधा प्रदान करेंगे।

03

हम श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु हर संभाग में एक **श्रमिक कल्याण कार्यालय** की स्थापना एवं हर जिले में **मोबाइल कैंप** का संचालन करेंगे।

04

हम 'छत्तीसगढ़ श्रमिक कल्याण बोर्ड' के कामकाज को नियमित कर प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाएंगे। साथ ही श्रमिकों, गिर्ग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स के हित में निजी कंपनियों से वार्ता कर कमीशन कैपिंग, परिवहन ईंधन के लिए प्रावधान और मनमाने ढंग से श्रमिकों की आईडी निष्क्रिय किए जाने पर रोक लगाएंगे।

05

हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक असंगठित श्रमिकों तक **सरकारी योजनाओं** के लाभ पहुंचाएंगे।



विकसित गाँव - विकासशील प्रदेश



— हमने किया —



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 2017 तक ₹2,170.73 करोड़ की लागत से 1,385 सड़कों का निर्माण किया।



2016 तक प्रदेश के गाँवों में 96.93% विद्युतीकरण कर 18,969 गाँवों तक बिजली पहुंचाई।



कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 2016 तक 3.7 लाख निःशुल्क विद्युत् पंप दिए।

हम ही कर रहे हैं



राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹626.32 करोड़ की निधि प्रदान की गई।



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2016 से 2019 तक कुल ₹9,603.14 करोड़ की निधि प्रदान की।



स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 35 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 38% घरों को नल-जल की उपलब्धता से वंचित रखा गया है।
- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 14वें और 15वें वित्त आयोग और रूबन मिशन के लिए जारी पैसा गोधन न्याय योजना में डाल कर कांग्रेस सरकार ने ₹1,300 करोड़ का दुर्खलयोग किया।
- कांग्रेस सरकार द्वारा 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए बजट का केवल 4.9 प्रतिशत ही आवंटित किया गया।



—हमारा वादा—

01

हम 2 सालों के अंदर '**घर-घर निर्मल जल अभियान**' की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के लंबित **18 लाख घरों** में पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगे।

02

हम '**ग्राम सड़क पुनरुद्धार योजना**' प्रारंभ कर प्रदेश के हर गाँव को सभी दिशाओं से बारहमासी सड़कों से जोड़ने एवं किसानों के खेत तक **पहुँच मार्ग (धरसा)** बनाने का काम करेंगे।

03

हम स्थानीय जनजातीय समुदायों को **सशक्त** बनाने एवं उनकी आय में वृद्धि लाने हेतु **फार्म-टूरिज्म** को बढ़ावा देंगे।

04

हम केंद्र के '**मिशन अमृत सरोवर**' की तर्ज पर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक **अमृत सरोवर** का निर्माण एवं पुनर्विकास करेंगे।

05

हम **PM-WANI** के माध्यम से छत्तीसगढ़ में **डिजिटल वाई-फाई हॉटस्पॉट** स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने का काम करेंगे।

06

हम प्रदेश के सभी गांवों में **सौर ऊर्जा** से चलने वाली **स्ट्रीट लाइट** लगाएंगे।



भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी

उत्तम स्वास्थ्य - सेहतमंद प्रदेश



हमने किया



वर्ष 2008 में शुरू की गई **मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना** के तहत 2017-18 तक राज्य में **6,748** से अधिक बच्चों की निःशुल्क इलाज करा जान बचाई जा चुकी है।



छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार **महतारी जनन योजना** से अनुमानित **1.54** लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुईं।



भाजपा राज्य सरकार के कार्यकाल में जिला अस्पतालों की संख्या 2001-02 में **7** से तीन गुना बढ़कर 2017-18 तक **26** हो गई।

हम ही कर रहे हैं



मोदी सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कुल **2.12** करोड़ से ज्यादा पहली और **2.03** करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज़ लगाई गई।



आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजे-एवाई) के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में **2.03** करोड़ स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं जिनमें से **1.05** करोड़ कार्ड महिलाओं को वितरित किये गये।



भाजपा की केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत **₹6,365.16** करोड़ जारी किए, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय आवंटन **₹949.94** करोड़ था।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस सरकार के दौरान इलाज के आभाव से प्रदेश में **39,000** से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई।
- कांग्रेस सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कुछ नहीं किया है।
- कांग्रेस सरकार के घोषणा के उलट 2019 में राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की गंभीर कमी थी। 2021 में केवल **319** विशेषज्ञ उपलब्ध थे और कमी आभी भी वैसी ही है।





हमारा वादा

01

हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत वार्षिक सीमा को दोगुना करके प्रति परिवार को ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख का स्वास्थ्य बिमा प्रदान करेंगे।

02

हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र बना कर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे।

03

हम छत्तीसगढ़ के हर संभाग में एस की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (CIMS) का निर्माण करेंगे।

04

हम प्रदेश के हर ब्लॉक में 'सिक्ल सेल स्क्रीनिंग सेंटर' स्थापित कर समस्या को जड़ से खत्म करेंगे और हर नागरिक को सिक्ल सेल एनीमिया कार्ड जारी किया जाएगा।

05

हम राज्य के हर ब्लॉक में एक डायलिसिस केंद्र सुनिश्चित करेंगे।

06

हम राज्य के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 150 मोबाइल क्लीनिक लॉच करेंगे, जिसमें जन-जागरूकता के लिए आदिवासी समुदाय से एक वालंटियर होगा।

07

राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना निःशुल्क संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया जाएगा।

08

हम छत्तीसगढ़ मेडिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू करके राज्य में 50 बेड से कम वाले अस्पतालों तथा नर्सिंग होम पर अनुपालन बोझ को कम करेंगे।

09

हम स्वास्थ्य विभाग के बजट आवंटन को बढ़ाकर दोगुना करेंगे।



बेहतर शिक्षा - उज्ज्वल भविष्य



हमने किया



भाजपा सरकार ने प्रदेश में IIT, IIIT, AIIMS एवं HNLU की स्थापना की।



वर्ष 2016-17 के लिए सरस्वती साइकिल योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 1,11,519 थी।



भाजपा सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की संख्या 4 से बढ़कर 2017-18 तक 17 हो गई।

हम ही कर रहे हैं



समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ₹4,838.29 करोड़ स्वीकृत किये गये थे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत, 2016-18 से, केंद्र सरकार द्वारा ₹621.88 करोड़ आवंटित किए गए थे।



केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 73 एकलव्य विद्यालय बनाए।



छत्तीसगढ़ में 2018-2020 तक नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि ₹2.61 करोड़ है।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी छात्रों के लिए परिवहन सुविधा मुफ्त करने के अपने घोषणापत्र के वादे पूरे करने में विफल रही।
- कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण योजना को भी रोक दिया है।
- कांग्रेस ने प्रदेश में लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त करने का वादा पूरा नहीं किया है।



हमारा वादा

01

हम छात्रों को कॉलेज आने-जाने के लिए **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर** के माध्यम से **मासिक ट्रेवल अलॉवंस** प्रदान करेंगे।

02

हम छत्तीसगढ़ के हर लोकसभा क्षेत्र में आई.आई.टी. की तर्ज पर **छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (CIT)** का निर्माण करेंगे।

03

हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद **57,000 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती** करेंगे।

04

हम हर जिले में '**प्रयास कोचिंग सेंटर**' स्थापित कर युवाओं को प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए **मुफ्त कोचिंग सुविधा** प्रदान करेंगे।

05

हम राज्य में **नई शिक्षा नीति** पूर्ण रूप से लागू करेंगे।

06

हम वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए सभी **स्कूलों** को **फिर से खोलेंगे।**

07

हम राज्य के हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के **विद्यार्थियों** के लिए **आवासीय व्यवस्था** सुनिश्चित करेंगे।

08

हम प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 से **करियर काउंसलिंग सुविधा** अनिवार्य करेंगे।



भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी

09

हम प्रदेश के हर बच्चे को **मुफ्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा** प्रदान करेंगे।

10

हम प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई में '**खाद्य एवं कृषि-व्यवसाय प्रबंधन**' जैसे पाठ्यक्रम शामिल करेंगे।

11

हम प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में **अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं** और सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **विज्ञान प्रयोगशालाएं** स्थापित करेंगे।

12

हम प्रदेश में **प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं** का लाभ उठाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को **₹5 लाख** तक बढ़ाएंगे।

13

हम '**छत्तीसगढ़िया हुनर स्कॉलरशिप**' के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग के छात्रों को **स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों** के लिए **टॉप 100 विदेशी विश्वविद्यालयों** में प्रवेश पाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

14

हम '**अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान**' की स्थापना कर छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक नीति इको-सिस्टम को मजबूत करेंगे।

15

हम प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में **200-बेड के स्नातकोत्तर छात्रावास** स्थापित कर छात्र-छात्राओं के लिए **सस्ते और सुलभ आवास** प्रदान करेंगे।



16

हम 'छत्तीसगढ़ डिजिटल कौशल योजना' के माध्यम से हर जिले में **अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं** स्थापित कर प्रदेश में रोजगार अवसर बढ़ाएंगे।

17

हम सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करेंगे एवं सभी कर्मचारियों को **क्रमोन्नति** का लाभ देंगे।



भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी

वचनबद्ध सुशासन



— हमने किया —



भाजपा ने प्रदेश में लोक सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, छत्तीसगढ़ मोबाइल एप्प एवं इ-डिस्ट्रिक्ट जैसी सेवाओं की शुरुआत की।



सरकार ने राज्य में नक्सलवाद की स्थिति में काफी सुधार किया, जिसके कारण सरगुजा और जशपुर जिलों को माओवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया गया, और बस्तर में भी बड़ा बदलाव देखा गया।



भाजपा सरकार में पुलिस स्टेशनों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। यह 2001-02 में 301 से बढ़कर 2017-18 तक 447 हो गया।

हम ही कर रहे हैं



केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2021 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पूरा लाभ मिल रहा है।



राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत, छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी सरकार द्वारा 2017-18 और 2020-21 के बीच ₹1,158.73 करोड़ आवंटित किए गए थे।



प्रदेश में वामपंथी हिंसा में भारी गिरावट हुई है, 2009 में चरमपंथी हिंसा में कुल मिलाकर 1,005 लोग मारे गए जबकि 2021 में 147 लोग मारे गए।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस सरकार ने अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने वादे अनुसार नियमित नहीं किया है।
- कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद बढ़ा है। 2019 और नवंबर 2022 के बीच वामपंथी उग्रवाद से संबंधित कुल 1,112 अपराध हुए हैं।
- कांग्रेस सरकार ने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है, इसको लेकर पुलिसकर्मियों ने आक्रोशित होकर आंदोलन भी किया।



हमारा वादा

01

हम प्रदेश में "सरकार तुंहर दुवार" योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर **1.5 लाख बेरोज़गार युवकों को भर्ती** कर प्रभावी घर पहुँच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेंगे।

02

हम सरकार बनने के **100 दिनों** के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की **समीक्षात्मक प्रक्रिया** आरम्भ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक **कमिटी** का गठन करेंगे जिसमें **अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी** भी सदस्य होंगे।

03

भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेस नीति -

1. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ **आयोग गठित** करेंगे।
2. भ्रष्टाचार **शिकायत निवारण व निगरानी** रखने के लिए एक **वेब पोर्टल** बनाएंगे।
3. प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु **मुख्यमंत्री कार्यालय** में एक **सेल** का गठन करेंगे।

04

हम सरकार बनाते ही भ्रष्टाचार और गैर कानूनी रूप से हुई सरकारी भर्तियों की समयबद्ध रूप से जांच करवाकर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई एवं दंड सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रणाली लागू करेंगे।

05

हम प्रदेश के अधिवक्ताओं एवं डॉक्टरों के हित की रक्षा के लिए **अधिवक्ता एवं डॉक्टर सुरक्षा कानून** लाएंगे।

06

हम **पंचायत सचिवों** को **नियमित** करेंगे एवं उनका बकाया एरियर **पी.पी.एफ.** में जोड़ा जाएगा।

07

हम प्रदेश में शिकायतों के दर्ज किए जाने एवं त्वरित जांच हेतु ADG स्तरीय अफसरों के देख रेख में **ऑनलाइन FIR प्रणाली** शुरू करेंगे एवं **फ़र्ज़ी मुकदमों** को **समाप्त** कर ऐसे शिकायतकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

08

हम प्रदेश में भूमि सम्बन्धी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए **ज़िला मुख्यालयों में भूमि थाना** एवं **भूमि न्यायालय की स्थापना** करेंगे एवं किसानों के नामांतरण, फौती, त्रुटी सुधार, नक्शा सुधार, सीमांकन जैसी समस्याओं का **लोक सेवा अधिनियमों** के अंतर्गत समयबद्ध निपटारा किया जाएगा।



09

हम छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित अपराधों के लिए न्यूनतम **दस साल का कठोर कारावास** (आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) और कम से कम **5 लाख रुपये का जुर्माना** सुनिश्चित करते हुए सख्त कानून लागू करेंगे।

10

हम वर्तमान सरकार द्वारा बेची गई **सरकारी जमीनों की जांच** कराएंगे।

11

हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले **डी.ए. के समान डी.ए.** देंगे।

12

हम तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस क्वार्टरों के निर्माण हेतु **पुलिस कल्याण कोष** को सशक्त करेंगे।

13

हम "**छत्तीसगढ़ माफिया और अन्य संगठित अपराध (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम**" (CG-MOCA) नामक एक विशेष कानून बना आपराधिक सिंडिकेट और संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे।

14

सुशासन फेलोशिप की शुरुआत कर हर दो साल में छत्तीसगढ़ से **50 प्रोफेशनल्स** का चयन किया जाएगा।

15

हम '**ई-लोकायोग**' ऐप की शुरुआत कर नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सीधे दर्ज करने के लिए एक साधन प्रदान करेंगे।

16

हम प्रदेशवासियों की **जाली चिट फण्ड** में **फंसी राशि** की 5 सालों के अंदर वापसी सुनिश्चित करेंगे।

17

हम केंद्र सरकार से **मितानिन (आशा)** कर्मचारियों को NHM के अंतर्गत स्थाई रूप से लिए जाने का निवेदन करेंगे।



18

हम प्रदेश में शासकीय नौकरियों की **लेटरल एंट्री हेतु नीति** बनाकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के दो चरण पास (Mains) कर चुके छत्तीसगढ़ी छात्रों को प्राथमिकता देंगे।

19

हम सभी वेतनमान कर्मचारियों की **वेतन एवं पेंशन** महीने की 15 तारीख से पहले प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

20

हम **मितानिन कर्मचारियों** की मासिक मानदेय राशि में **50 प्रतिशत की वृद्धि** करेंगे तथा उन्हें **पर्याप्त स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण** प्रदान करेंगे।

21

हम शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाईकर्मी एवं मध्यान्ह भोजन वाले रसोइयों के वेतन में **50% की वृद्धि** करेंगे।



भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी

मजाबूत बुनियाद - अदृट संरचना



हमने किया



भाजपा सरकार में मुख्य ज़िलों की सड़कों में **5 गुना** बढ़ोतरी हुई।



भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ देश का पहला जीरो पावर-कट राज्य बना।



भाजपा सरकार के दौरान राज्य में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में **7.6 गुना** इजाफ़ा हुआ, वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में **146 मोबाइल टावर** का निर्माण किया गया।

हम ही कर रहे हैं



सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्य के **99%** घरों तक बिजली पहुंचाई गई।



भारतमाला योजना के तहत प्रदेश में ₹**12,700 करोड़** की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।



प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत ₹**4,810 करोड़** की केंद्रीय सहायता से राज्य में 3 लाख से अधिक घरों के निर्माण को स्वीकृति दी।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस कृशासन के कारण छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धन की उपलब्धता के बावजूद प्रधानमंत्री आवास ठीक से लागू नहीं हो रही हैं।
- कांग्रेस सरकार के अंतर्गत प्रदेश में सड़क निर्माण बेहद धीमी गति से हो रहा है जिसके कारण राज्य का विकास दर कम हो गया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की भूमि अधिग्रहण में उदासीन रवैया अपनाने के कारण राज्य में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं रुक गई हैं।





हमारा वादा

01

हम नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली (NCR) की तर्ज पर **स्टेट कैपिटल रीजन (SCR)** की स्थापना कर **रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र** का समन्वित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करेंगे।

02

हम "**शहरी समृद्धि योजना**" की शुरुआत कर अत्याधुनिक **शहरी प्रशासन प्रणालियों** के माध्यम से स्वच्छ और समावेशी शहर बनाएंगे।

03

हम **जल-जमाव-मुक्त छत्तीसगढ़** बनाने हेतु जिला स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण एवं निगरानी के लिए केंद्रीकृत एकल-खिड़की सिस्टम स्थापित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में सीवरों की सफाई 'मैनहोल से मशीन-होल मोड' से सुनिश्चित करेंगे।

04

हम 2027 तक प्रदेश के प्रत्येक राज्य राजमार्ग को **बारहमासी उपयुक्त** एवं चारपहिया वाहनों के लिए सक्षम बनाएंगे।

05

हम प्रदेश में एक व्यापक '**ईवी पॉलिसी**' बनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुल **35% सब्सिडी** प्रदान करेंगे।

06

हम प्रदेश में भाजपा कार्यकाल की तरह 24x7 बिजली आपूर्ति एवं अनियमित **बिजली बिलों से राहत** सुनिश्चित करेंगे।

07

हम हर जिले में **इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर** की स्थापना कर '**24x7 सीसीटीवी निगरानी**' के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।

08

हम '**छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति**' लागू कर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का तेजी से एकीकृत विकास सुनिश्चित करेंगे।



वैभवपूर्ण विरासत - वंदनीय छत्तीसगढ़



हमने किया



पर्यटकों की संख्या और रोज़गार बढ़ाने के उद्देश्य से **रमन जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना** की शुरुआत 2016 में की गई।



2018 में **आदिवासी संस्कृति की रक्षा** के लिए राज्य भर में **150 'देवगुड़ी' (पवित्र उपवन)** बनाने की घोषणा की।



2013 में **छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड** को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए **राष्ट्रीय पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया था।

हम ही कर रहे हैं



केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया।



'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान' (प्रसाद) योजना के तहत, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, डोंगरगढ़ के लिए ₹43.33 करोड़ दिया गया।



स्वदेश दर्शन के आदिवासी सर्किट थीम के तहत 2015-16 में छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ के विकास के लिए ₹96.10 करोड़ मंजूर किए हैं।

कांग्रेस का धोखा

- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है।
- कांग्रेस सरकार पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने में विफल रही है।
- अक्षम बुनियादी ढाँचे, असुरक्षित वातावरण और खराब ब्रांडिंग के कारण राज्य को पर्यटन क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है।



हमारा वादा

01

हम प्रदेश में **1,000 किलोमीटर लंबी 'शक्ति-पीठ परियोजना'** की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के पांच शक्ति पीठों को उत्तराखण्ड की **चार धाम परियोजना** की तर्ज पर विकसित करने और जोड़ने का काम करेंगे।

02

हम प्रदेशवासियों को **श्रीरामलला के दर्शन** कराने हेतु **अयोध्या लेकर जाएंगे।**

03

हम गिरौदपुरी अमृत कुंड से पंचकुण्डि होते हुए छाता पहाड़ को '**सतनाम मार्ग**' के रूप में विकसित करेंगे तथा **गिरौदपुरी धाम एवं छाता पहाड़** को **तीर्थ स्थल** में विकसित किया जाएगा।

04

हम **बांधा-मुंगेली** के गुरु बालक दास शहादत स्थल को **तीर्थ स्थल** के रूप में विकसित करेंगे।

05

हम प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में **मुक्तिधाम एवं दसगात्र** हेतु **हर घाट पर सुविधाओं में सुधार** करेंगे।

06

हम **राजिम माता मंदिर** परिसर के परिवर्त स्थल का जीर्णोद्धार एवं **राजिम के अटल घाट** का विकास कर **त्रिवेणी संगम** की भव्यता को बढ़ाएंगे।

07

हम प्रदेश में **शिल्पकारों और कारीगरों** के हित में **पीएम विश्वकर्मा योजना** के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ में वृद्धि करेंगे एवं '**पौनी पसारी समृद्धि योजना**' की शुरुआत कर पारम्परिक व्यवसायियों को स्वरोज़गार हेतु अनुदान प्रदान करेंगे।



08

हम ₹100 करोड़ का 'लोक कलाकार कल्याण कोष' (एंडोवर्मेंट फण्ड) का गठन करेंगे जिससे पारंपरिक एवं लोक प्रदर्शन कलाओं के शिक्षण और मंच कलाकारों के लिए प्रोत्साहन राशि का अनुदान होगा।

09

हम प्रदेश में पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसरों को पैदा करेंगे।

10

हम 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' का पुनः आरम्भ कर प्रदेश में सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को तीर्थयात्रा करवाएंगे।

11

हम जनजातीय समुदायों की भूमि और देव गुड़ियों के संरक्षण हेतु व्यवस्था करेंगे साथ ही प्रत्येक देव गुड़ी के लिए ₹5 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान कर राज्य में सभी देव गुड़ियों को मजबूत करेंगे।

12

हम प्रदेश के मंदिरों एवं मंदिरों में स्थित तालाबों और झीलों का जीर्णोद्धार कर मंदिरों की सुंदरता को बढ़ाएंगे।

13

हम प्रदेश में "महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार" एवं "कुमार दिलीप सिंह जूदेव पुरस्कार" की शुरुआत कर धर्मान्तरित व्यक्तियों को पुनः मूल धर्म से जोड़कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा करने वाले निजी संगठनों एवं व्यक्तियों को इनाम राशि प्रदान करेंगे।



14

हम 'छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मार्केटिंग सेल' की स्थापना कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे।

15

हम ₹100 करोड़ के कॉर्पस फंड के साथ एक "जनजाति संस्कृति संस्थान" (जेएसएस) की स्थापना कर अनुसंधान एवं रचनात्मक प्रकाशन के माध्यम से जनजातीय इतिहास, कला, संस्कृति तथा जीवन शैली को संहिताबद्ध करने और बढ़ावा देने का

16

हम प्रदेश में ललित कला अकादमी की शाखा की स्थापना करने का प्रयास करेंगे।

17

हम प्रदेश में 'हैन्डीक्राफ्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024' लागू कर कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए मार्केटिंग एवं इनोवेशन पर विशेष जोर देंगे।

18

हम रायगढ़ में विश्व स्तरीय 'महाराजा चक्रधर कला एवं संगीत अकादमी' की स्थापना कर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध एवं संरक्षित कर उसे बढ़ावा देंगे।

19

हम प्रदेश में छत्तीसगढ़ फिल्म एवं टेलीविज़न बोर्ड का गठन कर एक फिल्म सिटी तथा FTII की तर्ज पर एक अकादमी का निर्माण करेंगे।

20

हम प्रदेश में पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली इत्यादि को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे।



ऊर्जावान युवा - प्रगतिशील प्रदेश



हमने किया



अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 27 ज़िलों में लाइबलीहूड कॉलेज शुरू किए।



छत्तीसगढ़ 'कौशल के अधिकार' को मौलिक प्रावधान के साथ 'छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम' पारित करने वाला 2013 में देश का पहला राज्य बना।



भाजपा के कार्यकाल में कई खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू और पूरी की गईं।

हम ही कर रहे हैं



आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2023 तक छत्तीसगढ़ में कुल 85,083 कर्मचारियों के साथ 2,949 प्रतिष्ठान लाभान्वित हुए हैं।



दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत कुल 56,028 ग्रामीण उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।



2023 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत कुल 82,560 युवाओं को रोजगार मिला था।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस ने पीएससी घोटाला कर छत्तीसगढ़ के योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।
- भाजपा सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया था वहीं कांग्रेस सरकार के उदासीन रूपैया अपनाने के कारण स्टेडियमों की हालत बदतर हो गई है।
- भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप शुरू की थी और कांग्रेस ने इसे बंद कर दिया है।





हमारा वादा

01

हम दो वर्षों में प्रदेश के सभी रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेंगे।

02

हम "छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना" के तहत प्रदेश में युवाओं को **50% सब्सिडी** के साथ **ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान करेंगे।

03

हम राज्य में पी.एस.सी. और व्यापम जैसी सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु UPSC की तर्ज पर **वार्षिक कैलेंडर** की **शुरुआत** करेंगे एवं हर ब्लॉक में कम से कम **एक परीक्षा केंद्र स्थापित** करेंगे।

04

हम छत्तीसगढ़ के **लाइवलीहुड कॉलेजों** में **कला स्टूडियो** स्थापित कर राज्य के 'डिजिटल इंफल्युएंसर्स', कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिस्ट समुदाय को सशक्त करने और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

05

हम "**छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना**" को पुनः लागू कर कॉलेज छात्र-छात्राओं को **निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट** प्रदान करेंगे।

06

हम राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीतने में मदद करने और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रायपुर में एक **अत्याधुनिक ओलंपिक प्रशिक्षण अकादमी** स्थापित करेंगे।

07

हम ब्लॉक स्तर पर शासकीय खेल मैदानों में **उच्च स्तरीय खेल उपकरणों** की उपलब्धता अनिवार्य करेंगे।



08

हम प्रत्येक जिले के लोकप्रिय खेलों के लिए **ज़िला-स्तरीय खेल अकादमियों** की स्थापना कर महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं को **प्रोफेशनल कोचिंग और मार्गदर्शन** प्रदान करेंगे।

09

हम '**छत्तीसगढ़ीय क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना**' की शुरुआत कर पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित एवं उन्नत करेंगे।

10

हम सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में कुल **5 बहुउद्देशीय स्टेडियम** स्थापित कर पारंपरिक खेलों की मेजबानी और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेंगे।

11

हम प्रत्येक ब्लॉक में **एस्ट्रोटर्फ-आधारित ओपन-एयर व्यायामशालाओं** का निर्माण कर स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित और खेल संस्कृति को विकसित करेंगे।

12

हम '**छत्तीसगढ़ खेल रत्न खोज अभियान**' की शुरुआत कर प्रदेश को खेल के केंद्र में बदलने हेतु:

1. रायपुर में राज्य का **पहला खेल विश्वविद्यालय** स्थापित किया जाएगा।
2. एक '**प्रतिभा खोज कार्यक्रम**' शुरू कर हर साल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें ₹75,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
3. एक **नई खेल नीति 2024**, के तहत ग्रामीण स्तर से पारंपरिक खेलों के लिए **आधारभूत संरचना** प्रदान की जाएगी एवं प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मानक खेल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

13

हम प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को **सरकारी भवित्वों में प्राथमिकता** देंगे।



14

हम प्रदेश में 'प्रशिक्षुता संवर्धन योजना' (अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम) की शुरुआत कर युवाओं को प्रशिक्षण के लिए चयनित करेंगे एवं मासिक वेतन के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे।

15

हम मान्यता प्राप्त राज्य एवं जिला खेल संघों की **नियमित सालाना अनुदान राशि** एवं खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली **राशि समय पर प्रदान** करेंगे।

16

हम प्रदेश में खेल दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट **खेल अलंकरण समारोह** का पुनः आरम्भ करेंगे।



भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी

40

व्यापार वृद्धि से प्रदेश की समृद्धि



हम ही कर रहे हैं



नैशनल इन्फ्रार्मेटिक्स सेंटर ने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से सक्षम 28 केंद्र स्थापित किए हैं।



वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, छत्तीसगढ़ में पूर्ण/आंशिक रूप से होने वाले बुनियादी ढांचे और सुरक्षा कार्यों के लिए ₹3,730 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक बजट परिव्यय प्रदान किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय (₹311 करोड़/वर्ष) से 1,099% अधिक है।



01 जनवरी 2023 तक, छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत ₹12,700 करोड़ की लागत वाली 670 किमी लंबी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

कांग्रेस का धोखा

- प्रदेश में उद्योगों के विकास पर ध्यान देने के बजाय प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ते के नाम पर ठग रही है।
- आर्थिक विकास का अभिन्न अंग, सड़क बुनियादी ढांचे को राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है।
- कांग्रेस सरकार के तहत राजकोषीय घाटा 2017-18 में ₹9,647 करोड़ से बढ़कर 2023-24 तक ₹15,200 करोड़ हो गया है।



हमने किया

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत 2016 से फरवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ में 3,099 प्रतिष्ठानों और 1,32,291 कर्मचारियों को ₹118.07 करोड़ की सब्सिडी के माध्यम से योजना से लाभान्वित किया गया है।



छत्तीसगढ़ में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 2002-03 में 63,771 से बढ़कर 2017-18 तक 1,47,310 हो गई।



भाजपा शासनकाल में सीमेंट का उत्पादन 2001-02 में 86.3 लाख टन से बढ़कर 2017-18 तक 195.8 लाख टन हो गया यानी दोगुना से भी अधिक हो गया है।





—हमारा वादा—

01

हम **नया रायपुर** को **सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब** बना कर राज्य में 6 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे।

02

हम इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर **इन्वेस्ट छत्तीसगढ़** आयोजित करेंगे और **वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मलेन** कर **देशी व विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित** करेंगे।

03

हम राज्य में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु अत्याधुनिक '**आईटी पार्क**' स्थापित करेंगे।

04

हम "**छत्तीसगढ़ आईटी टैलेंट विकास योजना**" के माध्यम से विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और आकर्षक प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए **उद्योग-अकादमिक सहयोग** की सुविधा प्रदान करेंगे।

05

हम प्रदेश के हर जिले में '**छत्तीसगढ़िया उत्पाद उद्यमी केंद्र**' स्थापित कर एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और राज्य की राजधानियों में '**शॉप-सी.जी.**' ब्रांड नामक **उत्पाद स्टोर** खोलकर हर जिले को एक निर्यात केंद्र में विकसित करेंगे।

06

हम प्रदेश में ईवी क्रांति लाने हेतु अत्याधुनिक '**ईवी सिटी**' की स्थापना कर युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे।

07

हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लक्ष्य से प्रदेश में '**फार्मास्युटिकल पार्क**' स्थापित करेंगे।



08

हम प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस 'कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडर' स्थापित करेंगे।

09

हम प्रदेश के हर संभाग में **सब्ज़ी, खाद्य एवं कृषि-प्रसंस्करण पार्क** स्थापित कर छत्तीसगढ़ को **फूड प्रोसेसिंग** के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाएँगे और हवाई-कार्गो सुविधाओं से जोड़ेंगे।

10

हम प्रदेश में **बागवानी फसलों के घरेलू उत्पादन** को बढ़ावा देने और फसलों के स्वदेशी किस्मों पर विशेष ध्यान देने के लिए अमेरिका, नीदरलैंड और इजरायल की तर्ज पर एक '**स्वच्छ संयंत्र केंद्र**' स्थापित करेंगे।

11

हम छत्तीसगढ़ के हर जिले में **कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी** स्थापित करेंगे।

12

हम प्रदेश में '**निर्यात-विशिष्ट पैक हाउस**' स्थापित कर बागवानी उपज की अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाएंगे।

13

हम सालाना '**ग्लोबल छत्तीसगढ़ स्टार्टअप शिखर सम्मेलन**' आयोजित कर प्रदेश के महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए बेहतर वैश्विक नेटवर्क स्थापित कर युवाओं के लिए निवेश और रोजगार के अवसर में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

14

हम प्रदेश में '**अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब**' और '**नॉलेज प्रोसेस आउटसोसिंग (केपीओ)**' इकाईयां स्थापित कर राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेंगे।



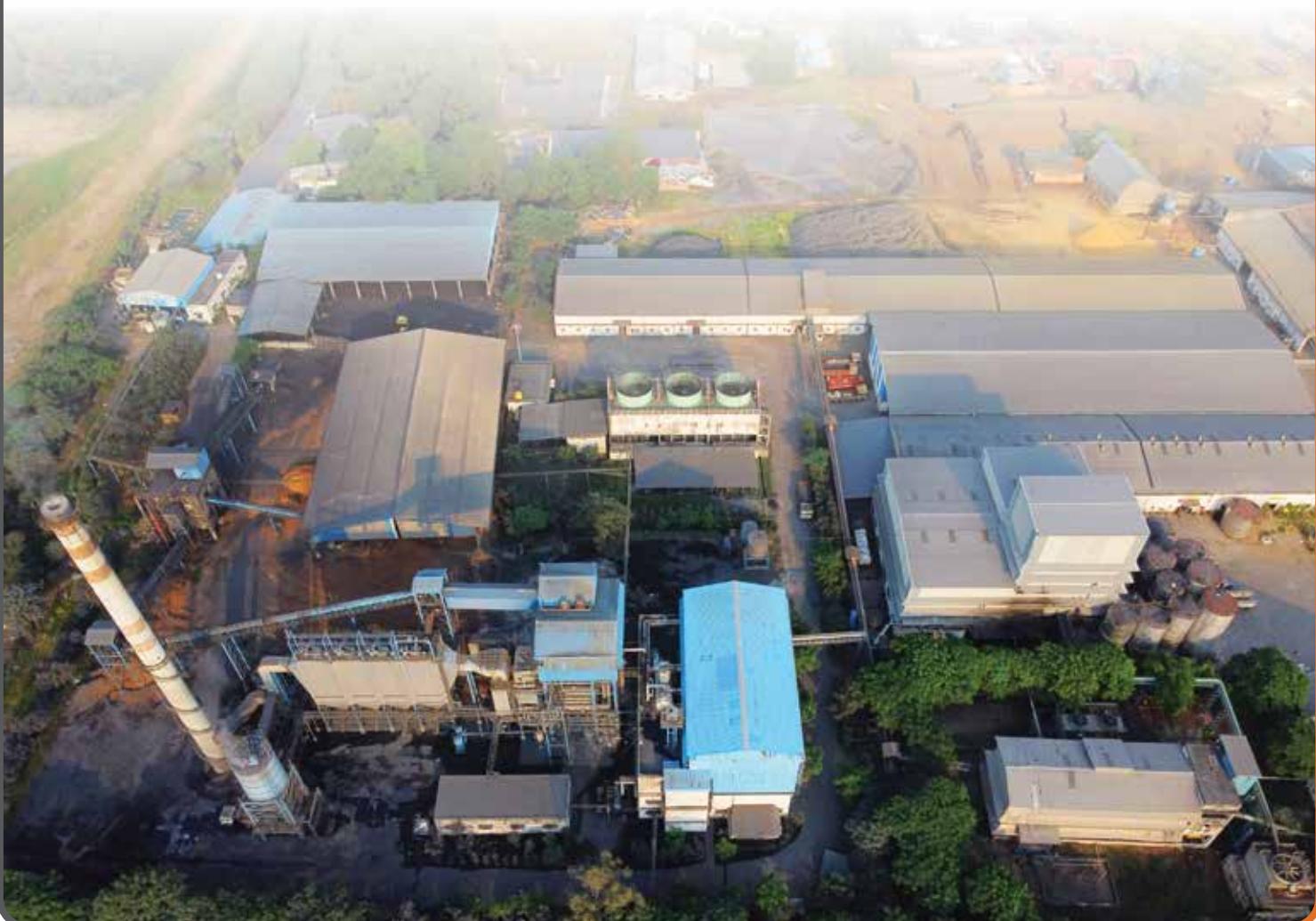
15

हम **सब्ज़ी एवं फल विक्रेता, अन्य स्ट्रीट वेंडर्स और गुमस्ता** की समस्याओं के निवारण हेतु एक **स्ट्रीट वेंडर कल्याण बोर्ड** का गठन कर छत्तीसगढ़ में स्ट्रीट वेंडरों और फेरीवालों को:

1. ₹2,000 की वार्षिक रखरखाव सहायता प्रदान करेंगे
2. एक '**सरलीकृत और पारदर्शी लाइसेंसिंग प्रक्रिया**' (एसटीएलपी) लागू कर रिश्वत की वसूली रोकेंगे तथा वेंडिंग स्थानों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करेंगे, एवं
3. उन्हें **सहयोग पोर्टल** में आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे।

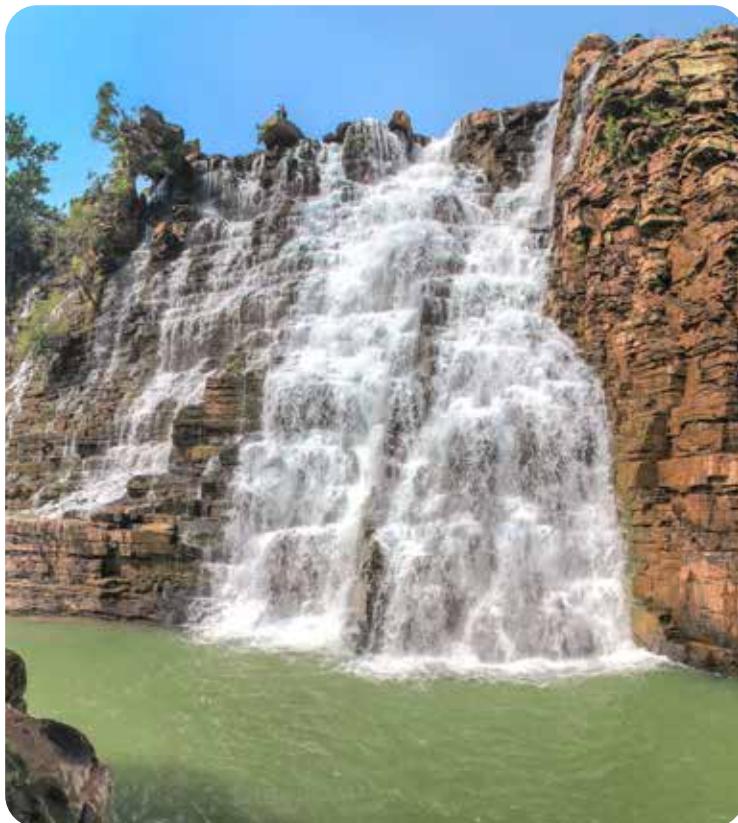
16

हम प्रदेश में **राइस मिल्स** को प्रोत्साहन देने हेतु अकार्यशील राइस मिलों को **कार्यशील, स्थापित राइस मिलों** का उन्नयन एवं नई मिनी राइस मिलों की स्थापना करेंगे।



भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी

प्राकृतिक संसाधन - प्रदेश का धन



हमने किया



वनों की बहाली के लिए, माजपा सरकार ने 2016-17 और 2017-18 के बीच ₹30.27 लाख आवंटित किए।



'हरियाली प्रसार योजना' के तहत माजपा सरकार ने 2016 से 2018 के बीच 5.96 करोड़ पौधे लगाए।



कोयला उत्पादन 2001-02 में 536.7 लाख टन से बढ़कर 2017-18 तक 1,425 टन हो गया।

हम ही कर रहे हैं



2019 से 2021 के बीच छत्तीसगढ़ वन विभाग को कैम्पा फंड के तहत कुल ₹1,200 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।



केंद्र सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 61.27 लाख पेड़ लगाए गए हैं।



नगर वन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 5 नगर पालिकाओं को परियोजना में शामिल किया गया है, जिसका कुल व्यय ₹5.72 करोड़ है।

कांग्रेस का धोखा

- कांग्रेस सरकार ने राजस्थान सरकार को परसा कांटा ब्लॉक में कोयला खनन करने की अनुमति दी है।
- कांग्रेस सरकार बस्तर में लौह अयस्क के खनन के कारण उत्पन्न हुए लाल पानी की समस्या से निपटने में भी विफल रही है।
- कांग्रेस सरकार ने जानवरों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके फल स्वरूप छत्तीसगढ़ देश में जानवरों के अवैध शिकार और जंगली जानवरों की खाल उतारने का गढ़ बन गया है।



—हमारा वादा—

01

हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश के हर छोटे-बड़े खनन से प्रभावित व्यक्ति को **रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा** समय पर उपलब्ध कराया जाए।

02

हम प्रदेश में जिला खनिज न्यास के तहत **प्रति दो वर्ष में अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)** और **वार्षिक जिला खनिज न्यास रिपोर्ट कार्ड** के प्रकाशन के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे।

03

हम खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश में आधुनिक निगरानी उपायों जैसे **ई-परमिट प्रणाली** और **जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली** को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

04

हम प्रदेश में एक विशेष '**रेत खनन निगरानी सेल**' (एस.एस.एम.सी.) स्थापित कर रेत खनन गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी (**रियल टाइम मॉनिटरिंग**) सुनिश्चित करेंगे।

05

हम जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) के दीर्घकालिक समाधान हेतु "**छत्तीसगढ़ क्लाइमेट जस्टिस मास्टरप्लान**" तैयार करेंगे जिसके तहत:

1. 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता को **5,000 मेगावाट** तक बढ़ाएंगे।
2. 2030 तक **कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी को 25%** तक बढ़ाएंगे।

06

हम प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रभावी और समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु '**छत्तीसगढ़ ग्रीन वॉर रूम**' की स्थापना करेंगे।



07

हम छत्तीसगढ़ खान और खनिज नियम, 2024 लागू कर राज्य में मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ावा देंगे और खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिक सुरक्षा मानदंडों को लागू करेंगे तथा स्थानीय इकाईओं एवं पंचायती राज संस्थानों के खनन सम्बन्धी अधिकार वापस दिलाएंगे।

08

एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो व्यापक परामर्श और लेमरू हाथी रिजर्व से जुड़े मुद्दों को हल करने हेतु सुझाव देगी।

09

हम वन संरक्षण और विकास योजना (वन-सेवी) बना 15 जिलों का चयन कर विकेन्द्रित और योजनाबद्ध तरीके से वन विकास और संरक्षण करेंगे।

10

हम जंगली हाथियों के कारण घर को हुए नुकसान के लिए शून्य-प्रीमियम 100% कवरेज बीमा एवं मानव-हाथी द्वन्द्व के कारण होने वाली मृत्यु के लिए ₹7,50,000 की अनुग्रह राशि प्रदान करेंगे।

11

हम मानव-पशु संघर्ष से कृषि उपज प्रभावित होने वाले किसानों को फसल क्षति कवर प्रदान करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल किया जाए।

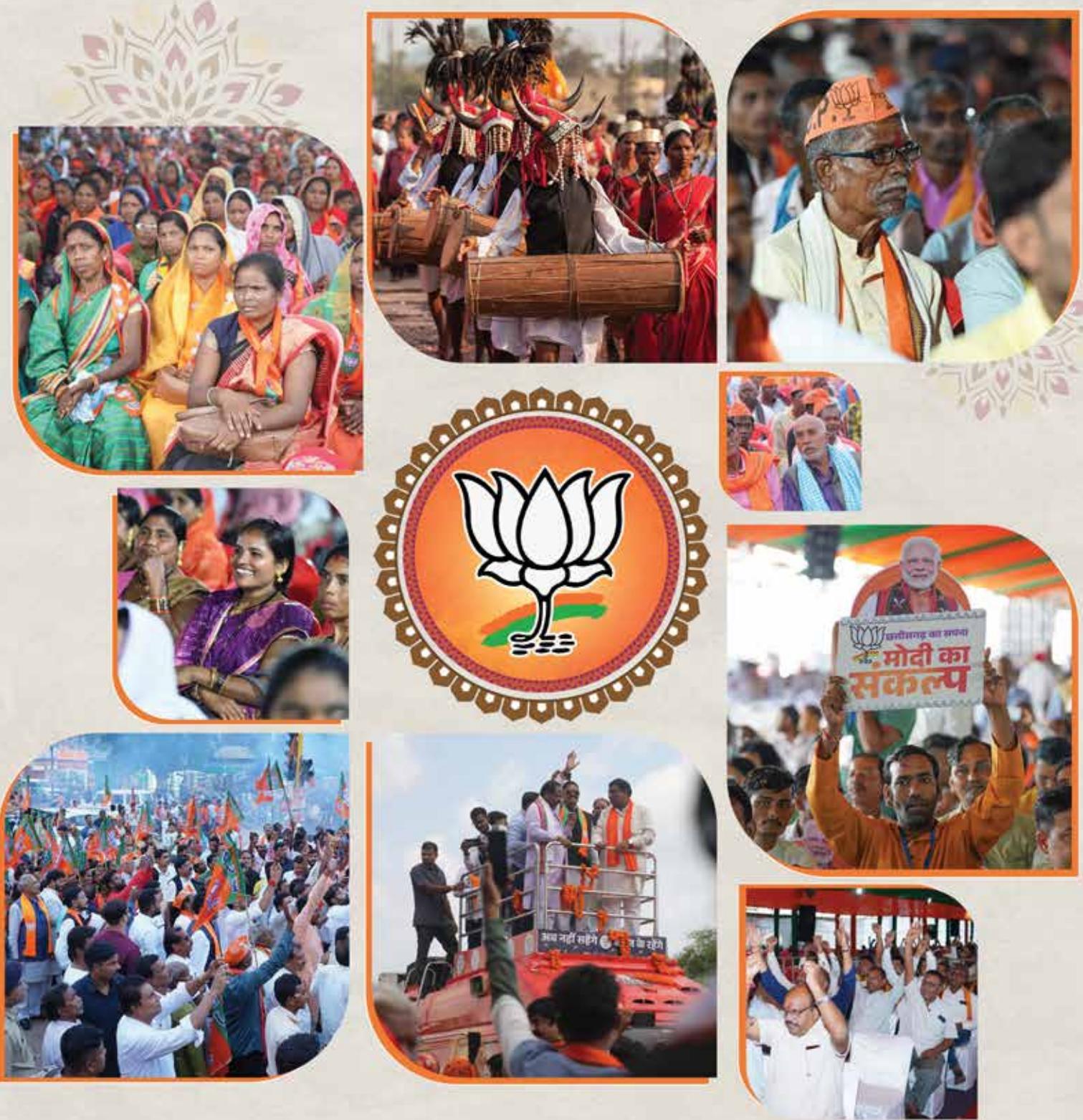
12

हम 'मिशन-बी' के माध्यम से मधुमक्खी बाड़ लगाकर प्रभावित गांवों में मानव-हाथी द्वन्द्व को रोकने का प्रयास करेंगे।

13

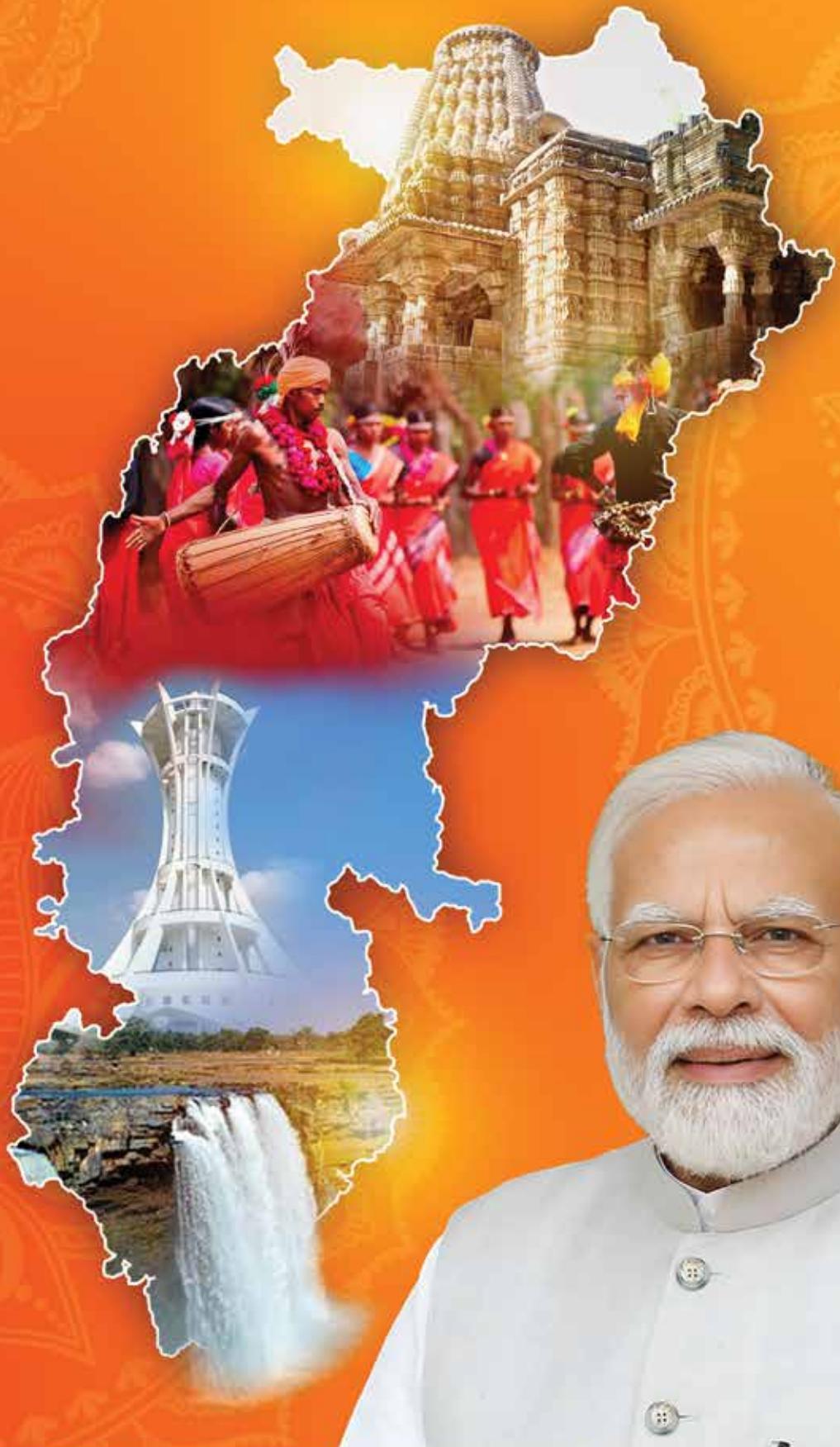
हम प्रदेश में 'प्रोजेक्ट बघवा' की शुरुआत कर बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने पर ध्यान देंगे।





तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़



भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़

कुशभाऊ ठाकरे परिसर, धमतरी रोड,
बोरियाकला 492015 रायपुर (सी.जी.)

